



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—SECTION 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2018/श्रावण 29, 1940
No. 313]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2018/SHRAVANA 29, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 6 अगस्त, 2018

सं. टीएमपी/39/2018-एमओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा मरमुगाव पत्तन न्यास (एमओपीटी) से पीओएल और पीओएल उत्पादों के घाट शुल्क प्रभारों के संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव का संलग्न आदेश के अनुसार निपटान करता है।

**महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण**  
मामला सं. टीएमपी/39/2018-एमओपीटी

मरमुगाव पत्तन न्यास

-----

आवेदक

**गणपति**

- (i) श्री टी एस बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

**आदेश**

(जुलाई, 2018 के 31वें दिन पारित)

यह मामला मरमुगाव पत्तन न्यास (एमओपीटी) के उनके पत्र संख्या एफए/कॉस्ट/125/2018/41 दिनांक 14 मई 2018 द्वारा पीओएल और पीओएल उत्पादों के घाट शुल्क प्रभारों के संशोधन से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने पत्तन के दरमानों के साथ एमओपीटी के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव का निपटान करते हुए 17 नवंबर 2016 को आदेश संख्या टीएमपी/38/2016-एमओपीटी द्वारा एक आदेश पारित किया। प्राधिकरण ने आदेश संख्या टीएमपी/38/2016-एमओपीटी दिनांक 17 नवंबर 2016 द्वारा अनुमोदित संशोधित दरमान और कार्यनिष्पादन मानकों को राजपत्र संख्या 434 दिनांक 30 नवंबर 2016 द्वारा अधिसूचित किया। तदनुसार, राजपत्र संख्या 15 दिनांक 12 जनवरी 2017 द्वारा एक सकारण आदेश अधिसूचित किया। यह दरमान भारत के राजपत्र में दरमान और कार्य निष्पादन मानकों की अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों अर्थात् 30 दिसंबर 2016 की समाप्ति के पश्चात् लागू हुई। इस दरमान की वैधता 31 मार्च 2019 तक है।

2.2. जैसा उक्त आदेश में बताया गया है एमओपीटी ने 433.37 करोड़ रुपए के संशोधित एआरआर के स्थान पर 199.80 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व का अनुमान लगाया है। इसमें 233.57 करोड़ रुपए के राजस्व अपेक्षा को अनकवर छोड़ दिया है। 233.57 करोड़ रुपए के राजस्व अंतर और प्रशुल्क में छूट जिसे पत्तन लौह अयस्क कार्गो हेतु देने के लिए सहमत हो गया है उसे लौह अयस्क व्यापार में वृद्धि के कारण से राजस्व से वसूली में शामिल कर दिया गया है। इस प्राधिकरण ने एमओपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित प्रशुल्क को दिनांक 17 नवंबर 2016 के आदेश में अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

3.1. अब इस पत्तन ने पीओएल और पीओएल उत्पादों की घाट शुल्क दर में संशोधन का प्रस्ताव किया है। एमओपीटी के दिनांक 14 मई 2018 के प्रस्ताव में उठाये गये बिंदुओं का सारांश इस प्रकार है:-

- (i) इस पत्तन ने अपने पत्र संख्या एफए/कॉस्ट/125/89 दिनांक द्वारा प्राधिकरण को इसके दरमानों में सामान्य संशोधन हेतु एक प्रस्ताव भेजा। प्रशुल्क नीति 2015 के अनुसार, 433.36 करोड़ रुपए की एआरआर की गणना की और तदनुसार वर्ष 2014-15 के 14.71 मिलियन टन कुल व्यापार पर आधारित दरमान प्राप्त की गई।
- (ii) कार्य प्रणाली के अनुसार कार्गो संबंधित सेवाओं (सीआरएस) और जलयान संबंधित सेवाओं (वीआरएस) की एआरआर पूरा करने के लिए मौजूदा दरमानों (तात्कालिक) में क्रमशः 240% और 106% की वृद्धि की आवश्यकता रही होगी। तथापि, प्रशुल्क में इतनी अधिक वृद्धि से व्यापार प्रभावित हो सकता था और इसलिए वीआरएस प्रभारों में 35% सीआरएस प्रभारों एवं भंडारण प्रभारों में 25% तक की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया। प्रभारों में वृद्धि 9% विशेष दर शामिल है और इसलिए जलयान संबंधित प्रभारों एवं कार्गो संबंधित प्रभारों में क्रमशः 26% और 16% की सकल वृद्धि हुई।
- (iii) प्राधिकरण ने आदेश संख्या टीएमपी/38/2016-एमओपीटी दिनांक 06.02.2017 द्वारा प्रस्तावित दरमान को अनुमोदन प्रदान किया और इस दरमान को दिनांक 12.01.2017 को राजपत्र संख्या 15 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचित किया। संशोधित दरमान 30 दिसंबर 2016 से लागू हुई और 31.03.2019 तक लागू रहेगी।
- (iv) **वर्तमान प्रस्ताव का विवरण:**  
यह पत्तन प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख टन पीओएल का प्रहस्तन कर रहा है और मौजूदा घाट शुल्क 193 रुपए प्रति टन है। पीओएल को बद्ध कार्गो माना गया है जिसकी दरें व्यापार को प्रभावित किए बिना बढ़ाई जा सकती है। इसलिए पीओएल कार्गो के घाटशुल्क को बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति टन करने का प्रस्ताव है।
- (v) **औचित्य:**
  - (क) यह पत्तन लौह अयस्क और कोयले का प्रहस्तन बंद होने से गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। उपरोक्त दरों में वृद्धि से पत्तन के राजपत्र में कुछ सीमा तक वृद्धि होगी। पत्तन की वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण से पीओएल की घाटशुल्क दर में वृद्धि उचित है।
  - (ख) इस प्राधिकरण द्वारा एमओपीटी के पहले से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार एआरआर का घाटा 233.57 करोड़ रुपए है। पीओएल की घाटशुल्क दर में प्रस्तावित वृद्धि से केवल 62.16 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसके बाद भी 171.41 करोड़ रुपए का घाटा है।
  - (ग) पीओएल दरों में वृद्धि से कार्गो का व्यापार प्रभावित नहीं होगा।
  - (घ) प्रति लीटर लागत लगभग 1.25 होगी जिसे उपयोगकर्ता पीओएल पर वसूल किए गए करें एवं शुल्कों पर विचार करते हुए वहन कर सकते हैं।
- (vi) एमओपीटी द्वारा मौजूदा दरमान में पीओएल और पीओएल उत्पादों की प्रस्तावित संशोधित घाट शुल्क दरें निम्नानुसार हैं:-

**2.1.3. तरल बल्क कार्गो**

क्र.सं.	वस्तुओं का विवरण	प्रति टन दर (रु.)	
		विदेशी कार्गो	तटीय कार्गो
1.	पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहक और पीओएल उत्पाद	1250.00	1250.00
2.	कास्टिक सोडा	86.00	51.60
3.	तरल अमोनिया	188.00	112.80
4.	सभी प्रकार के एसिड	128.00	76.80
5.	एलपीजी / एलएनजी	350.00	210.00
6.	खाद्य तेल	86.00	51.60
7.	सीरा	57.00	34.20
8.	कोई अन्य तरल बल्क कार्गो जिसका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है।	126.00	75.60

[यह वृद्धि केवल क्रम संख्या 1 पर पीओएल और पीओएल उत्पादों पर मौजूदा 193/-रुपए टन से 1250/-रु. प्रति टन प्रस्तावित है। एमओपीटी ने क्रम संख्या 2 से 8 हेतु कोई प्रस्ताव नहीं किया है।]

3.2. प्रस्ताव मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया है और मंडल का संकल्प शीघ्र ही भेज दिया जाएगा। इस प्राधिकरण से पीओएल और पीओएल उत्पादों के घाट शुल्क में संशोधन कर ऊपर तालिका में दर्शाए गए अनुसार 1250/-रु. प्रति टन करने का अनुरोध है:-

क्र.सं.	विवरण		टिप्पणियां
1.	एमओपीटी प्रस्ताव के अनुसार एआरआर (लाखों में)	43336.61	प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए फार्म I के अनुसार
2.	अनुमोदित दरमान से राजस्व अनुमान (लाखों में)	19979.63	प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए फार्म III के अनुसार
3.	एआरआर के संबंध में घाटा (लाखों रु. में) (1-2)	23356.98	
4.	वर्ष 2014-15 प्रहस्ति पीओएल की मात्रा (टन)	588074	प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए फार्म III के अनुसार
5.	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रति टन दर (रु.)	193.00	प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए फार्म III के अनुसार
6.	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान से अनुमानित घाट शुल्क (लाखों रु. में) (4X5)	1134.98	प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए फार्म III के अनुसार
	संशोधित प्रस्तावित दर (तटीय) (रु.)		
7.	पीओएल और पीओएल उत्पादों हेतु प्रस्तावित संशोधित घाट शुल्क प्रति टन	1250.00	
	<b>वृद्धि</b>	<b>₹</b>	<b>%</b>
8.	प्रति टन घाट शुल्क (7-5) (विशिष्ट वृद्धि)	1057.00	547.67
	प्रस्तावित संशोधन से अतिरिक्त राजस्व		

9.	बढ़ा हुआ घाट शुल्क (लाख रु. में) (1057 / टन x 5.88 टन)	6215.94	
10.	प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् एआरआर के संबंध में घाटा (लाख रु. में) (3-9)	17 141.04	

4. इस प्राधिकरण द्वारा आदेश संख्या टीएएमपी/38/2016-एमओपीटी दिनांक 17 नवंबर 2016 की अनुसूची 2.1.3 में तरल बल्क कार्गो हेतु गोदी में अनुमोदित घाट शुल्क का विवरण और एमओपीटी द्वारा पीओएल और पीओएल उत्पादों की घाट शुल्क दर में वांछित प्रस्तावित संशोधन को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:-

क्र.सं.	यह प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.11.2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/38/2016-एमओपीटी के तहत अनुमोदित तरल बल्क कार्गो दरें				एमओपीटी द्वारा दिनांक 14.05.2018 के उसके ई-मेल के तहत प्रस्तावित दरों में प्रस्तावित संशोधन			
1.	क्र.सं.	वस्तुओं का विवरण	प्रति टन दर (रु.)		क्र.सं.	वस्तुओं का विवरण	प्रति टन दर (रु.)	
			विदेशी कार्गो	तटीय कार्गो			विदेशी कार्गो	तटीय कार्गो
	1.	पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहक और पीओएल उत्पाद	193.00	193.00	1.	पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहक और पीओएल उत्पाद	1250.00	1250.00
	2.	कास्टिक सोडा	86.00	51.60	2.	कास्टिक सोडा	86.00	51.60
	3.	तरल अमोनिया	188.00	112.80	3.	तरल अमोनिया	188.00	112.80
	4.	सभी प्रकार के एसिड	128.00	76.80	4.	सभी प्रकार के एसिड	128.00	76.80
	5.	एलपीजी / एलएनजी	350.00	210.00	5.	एलपीजी / एलएनजी	350.00	210.00
	6.	खाद्य तेल	86.00	51.	6.	खाद्य तेल	86.00	51.60
	7.	सीरा	57.00	34.20	7.	सीरा	57.00	34.20
	8.	कोई अन्य तरल बल्क कार्गो जिसका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है।	126.00	75.60	8.	कोई अन्य तरल बल्क कार्गो जिसका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है।	126.00	75.60

5.1. प्रस्ताव स्वीकार करते समय एमओपीटी को हमारे दिनांक 17 मई 2018 के पत्र द्वारा मंडल के अनुमोदन की प्रति अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया था। पत्तन ने मंडल के अनुमोदन की प्रति प्रेषित नहीं की है।

5.2. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित उपयोगकर्ता/ उपयोगकर्ता संगठनों को दिनांक 17 मई 2018 के हमारे पत्र द्वारा दिनांक 14 मई 2018 के एमओपीटी के प्रस्ताव की प्रति अग्रेषित की गई थी। हमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के दिनांक 22 मई 2018 के उनके ई-मेल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के दिनांक 23 मई 2018 एवं दिनांक 25 मई 2018 के उनके पत्र के द्वारा टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। एचपीसीएल और आईओसीएल से प्राप्त टिप्पणियों को फीडबैक सूचना के रूप में एमओपीटी को अग्रेषित कर दिया गया है। एमओपीटी ने अपनी टिप्पणियां नहीं दी हैं।

5.3. एचपीसीएल और आईओसीएल ने दिनांक 22 मई 2018 और 23 मई 2018 के अपने ई-मेल के द्वारा अधिमानतः जून 2018 के प्रथम सप्ताह के दौरान उद्योग के सदस्यों के साथ विषयक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का अनुरोध किया है। इस संबंध में, हमने दिनांक 24 मई 2018 के अपने पत्र द्वारा एचपीसीएल और आईओसीएल को सूचित किया कि प्राधिकरण द्वारा पालन की गई

परामर्शक प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ता संगठन को संयुक्त सुनवाई के दौरान सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसलिए, एचपीसीएल और आईओसीएल में संयुक्त सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और संयुक्त सुनवाई में प्रस्ताव पर टिप्पणियाँ/मत देने का अनुरोध किया गया।

6. इस मामले में दिनांक 14 जून 2018 को एमओपीटी परिसर में एक संयुक्त सुनवाई की गई। एमओपीटी ने अपने प्रस्ताव का एक संक्षिप्त पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण दिया और आईओसीएल, एचपीसीएल एवं बीपीसीएल सहित संबंधित उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों ने अपने निवेदन रखे।

7.1. संयुक्त सुनवाई में बनी सहमति के अनुसार, 20 जून 2018 को एमओपीटी से आरादर में वृद्धि की मात्रा पर सहमति बनाने और एक सप्ताह में अर्थात् 22 जून 2018 तक उत्तर देने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद दिनांक 27 जून 2018 को एक स्मरण-पत्र प्रेषित किया गया।

7.2. आगे, एमओपीटी से दिनांक 27 जून 2018 के पत्र में पेट्रोलियम तेल और स्नेहक एवं पीओएल उत्पादों पर 1250/-रुपए प्रति टन की प्रस्तावित घाट शुल्क दर के समर्थन में लागत विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। एमओपीटी द्वारा लागत गणना प्रस्तुत करते समय, पूर्व प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए फार्म-5 के अनुसार साधारण व्यय विभाजन का सामान्य सिद्धांत अपनाया गया है। मामले के संदर्भ के लिये एमओपीटी को असंगत मदों को हटाकर विधिवत संशोधित फार्म-5 की एक प्रति भी प्रेषित की गई। एमओपीटी को वर्ष 2017-18 में एमओपीटी द्वारा प्रहस्तित पीओएल और पीओएल उत्पादों की वास्तविक मात्रा एवं वर्ष 2018-19 के लिए अनुमान का भी उल्लेख करने का अनुरोध किया गया। एमओपीटी से 1 जुलाई 2018 तक आवश्यक सूचना प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है।

8.1. ऊपर पैरा 7.1 में, संयुक्त सुनवाई में निर्णित कार्रवाई बिंदुओं के संदर्भ में, एमओपीटी अपने 4 जुलाई 2018 के ई-मेल में सूचित किया कि पीओएल कार्गो के घाट शुल्क प्रभार में वृद्धि की मात्रा पर एक सहमति बनाने के लिए 3 जुलाई 2018 को तेल पीएसयू के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। एमओपीटी में पीओएल कार्गो के घाट शुल्क प्रभारों के संशोधन के लिए 03 जुलाई 2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त बैठक की विशिष्टतायें इस प्रकार हैं:-

- (i) आईओसी ने बताया कि पीओएल कार्गो पर प्रस्तावित घाट शुल्क प्रभारों में वृद्धि का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं है। सभी तीनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने घाट शुल्क की वर्तमान दर (193/- रु. प्रति एमटी) को जारी रखने का अनुरोध किया जो 31.03.2019 तक वैध है। तत्पश्चात् 5-10% की वृद्धि के अनुमोदन की संस्तुति की जाती है।
- (ii) तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि पीओएल कार्गो घाटशुल्क प्रभारों में इतनी अधिक वृद्धि थोपी जाती है तो उन्हें परिवहन के अन्य वैकल्पिक साधनों को तलाशना होगा और कार्गो को पत्तन से दूसरे मार्ग पर ले जाना होगा।
- (iii) पत्तन ने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों को यह संसूचित किया कि घाटशुल्क प्रभार में यह वृद्धि अस्थायी है जब तक पत्तन की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। आगे और सूचित किया गया कि प्रस्तावित दर अधिकतम है जिसे बाजार की स्थितियों में परिवर्तन के आधार पर घटाया भी जा सकता है। पत्तन नहीं चाहता कि कोई कार्गो अपरवर्तित किया जाए। लेकिन, निराधार वित्तीय स्थिति ने पत्तन को ऐसे कदम उठाने को बाध्य कर दिया है जो पत्तन को संभलने में सहायक हों, चाहे वे सीमांत ही क्यों न हों।
- (iv) पत्तन ने वर्तमान घाट शुल्क को संशोधित न करने का प्रस्ताव भी किया परंतु अतिरिक्त उप-कर/प्रभार की उगाही पत्तन की स्थिति में सुधार तक एक नियत अवधि तक की जायेगी।
- (v) तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि तेल कंपनियां इस अत्यधिक वृद्धि को सहन नहीं कर पायेंगी। उन्हें अनुरोध किया गया कि अपने-अपने मुख्य कार्यालयों को संसूचित करें कि पीओएल कार्गो पर घाट शुल्क प्रभारों में यह वृद्धि अस्थायी है और तब तक है जब तक पत्तन की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हो जाता और वित्तीय संकट के इस समय में तेल पीएसयू से सहायता की मांग की।

8.2. ऊपर पैरा 7.2 में हमारे 27 जून 2018 के पत्र द्वारा सूचित कार्रवाई बिंदु के संदर्भ में, एमओपीटी ने अपने 30 जून 2018 के पत्र के द्वारा निवेदन किया कि पीओएल कार्गो के 1250/- रु. प्रति एमटी की प्रस्तावित घाट शुल्क दर लागत परिकलन पर औचित्यपूर्ण नहीं है। तथापि निम्नलिखित पृष्ठभूमि में यह दर औचित्यपूर्ण है:

- (i) पत्तन की लाभदायकता में सुधार के लिए पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नियुक्त परामर्शदाता ने पीओएल प्रभारों में वृद्धि का सुझाव दिया।
- (ii) प्रस्तावित 1250/-रु. प्रति एमटी की प्रस्तावित घाट शुल्क दर प्रशुल्क संशोधन दिशानिर्देश 2015 के अनुसार निकाले गए 433.36 करोड़ रुपए के एआरआर के भीतर है।

- (iii) पत्तन वित्तीय दबाव में है और बर्थ नं. 6 पर लौह अयस्क खनन और कोयला प्रहस्तन पर प्रतिबंध के कारण राजस्व सृजित करने में असमर्थ है।
- (iv) पत्तन की हानियां 563 करोड़ रु. की हो गई है और 1700 कर्मचारियों को वेतन और 4300 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान करना है।
- (v) पीओएल बद्ध कार्गो है और पत्तन की प्रहस्तन लागत 1.30 रु. प्रति लीटर (लगभग) पड़ती है।
- (vi) इस समय, पीओएल पर लगाये गए कर और शुल्क उत्पादन लागत का 100% है तथा विक्रेता का मार्जिन 3/-रु. प्रति लीटर है।
- (vii) इन सब लागतों के बावजूद गोवा में पीओएल की कीमतें देश में सबसे कम है और इससे मांग प्रभावित नहीं होती।

9. तत्पश्चात, एमओपीटी ने अपने 24 जुलाई 2018 के पत्र द्वारा घाट शुल्क दर को 1250/- रु. प्रति टन से नीचे की ओर संशोधित करके 500/- रु. प्रति टन कर दिया। संशोधित प्रस्ताव का ब्यौरा इस प्रकार है:-

- (i) पत्तन ने पीओएल घाट शुल्क दर 1250/- रु. प्रति टन बढ़ाने के लिए प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तदनुसार, प्राधिकरण ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) सहित सभी हितधारकों के साथ एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया। चूंकि पत्तन और ओएमसी के बीच कोई सहमति नहीं हुई, प्राधिकरण ने एमओपीटी और ओएमसी के बीच एक और बैठक की सलाह दी ताकि वृद्धि की मात्रा पर सहमति बन सके। वह भी अनिर्णायक सिद्ध हुई।
- (ii) इस मुद्दे पर परामर्शदाता से चर्चा की गई और उनकी रिपोर्ट के आधार पर पीओएल कार्गो पर घाटशुल्क की दर 500/- रु. प्रति टन उगाही जा सकेगी। इसलिए, पत्तन ने पूर्व के प्रस्ताव को संशोधित करने की इच्छा प्रकट की और पीओएल उत्पादों पर प्रस्तावित घाटशुल्क को 1250/-रु. प्रति टन से घटा कर 500/-रु. प्रति टन करने का प्रस्ताव किया है।

#### **प्रस्ताव का ब्यौरा:**

- (iii) पीओएल को एक बद्ध कार्गो के रूप में चिह्नित किया गया है और तेल कंपनियों के लिए गोवा राज्य को पीओएल मुहैया कराने के लिए अन्य साधनों को अपनाना इतना आसान नहीं है। इसलिए, पीओएल पर घाटशुल्क दरों को कार्गो को आद्योपांत प्रभावित किये बिना वृद्धि की जा सकती है। इसलिए पीओएल कार्गो पर 193/-रु. प्रति टन के घाटशुल्क को बढ़ाकर 500/- रु. प्रति टन किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है। पत्तन लगभग 6 लाख टन पीओएल का प्रति वर्ष प्रहस्तन करता है।
- (iv) (क) लौह अयस्क और कोयला प्रहस्तन पर रोक लग जाने के कारण पत्तन गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। उक्त दरों में वृद्धि से कुछ हद तक पत्तन के राजस्व में वृद्धि होगी।
  - (ख) पत्तन लागतों को कम करने के लिए, अन्य लौह अयस्क और कोयला व्यापार के हितधारकों की तरह अपने कर्मचारियों की कामबंदी नहीं कर सकता और उसे भारी संख्या में कार्यबल को रखना ही पड़ेगा, जो एक स्थायी लागत है।
  - (ग) पत्तन का पेंशनर पर व्यय प्रति वर्ष लगभग 100.00 करोड़ रुपए है जिस पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है।
  - (घ) अपने कर्मचारियों पेंशनरों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने पर पत्तन का व्यय प्रति वर्ष लगभग 18.00 करोड़ रुपए तक का है।
  - (ङ) एमओपीटी के प्रस्ताव के अनुसार एआरआर के संबंध में 233.57 करोड़ रु. का घाटा पहले ही प्राधिकरण ने अनुमोदित किया है जबकि प्रस्तावित वृद्धि से मात्र 18.05 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व सृजित होगा फिर भी घाटा 215.52 करोड़ रु. का रहता है।
  - (च) पीओएल दरों में वृद्धि से कार्गो पर आद्योपांत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  - (छ) पत्तन की वर्तमान वित्तीय स्थिति पीओएल की घाट शुल्क दरों में वृद्धि चाहती है।
  - (ज) प्रति लीटर घाट शुल्क 0.50 पैसा पड़ेगी, जो पीओएल पर करों और शुल्कों को देखते हुए प्रयोक्ताओं के लिए वहनीय है।
  - (झ) पीओएल एक स्वच्छ कार्गो है और गोवा में इसकी कीमतें देश भार से कम हैं। स्वच्छ गोवा के लिए 0.50 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि बहुत छोटी सी कीमत है।

- (व) प्रस्तावित दर अधिकतम दर होगी और व्यापारिक परिदृश्य में परिवर्तन के साथ रियायतें दी जा सकती हैं। संशोधित दरमान इस प्रकार है:

### 2.1.3. तरल बल्क कार्गो:

क्र.सं.	वस्तुओं का विवरण	दर प्रति टन (रु.)	
		विदेशी कार्गो	तटीय कार्गो
1.	पेट्रोलियम, तेल एवं लेहक और पीओएल उत्पाद	500.00	500.00
2.	कास्टिक सोडा	86.00	51.60
3.	तरल अमोनिया	188.00	112.80
4.	सभी प्रकार के एसिड	128.00	76.80
5.	एलपीजी / एलएनजी	350.00	210.00
6.	खाद्य तेल	86.00	51.60
7.	सीरा	57.00	34.20
8.	कोई अन्य तरल बल्क कार्गो जिसका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है।	126.00	75.60

[एमओपीटी द्वारा प्रस्तावित यह वृद्धि केवल क्रम संख्या 1 के लिये है।]

- (v) पीओएल प्रभागों में प्रस्तावित दर संशोधन के प्रभाव को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण नीचे दिया जाता है:-

क्र.सं.	विवरण		टिप्पणियाँ
1.	एमओपीटी प्रस्ताव के अनुसार एआरआर (लाख रु. में)	43336.61	प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए फार्म I के अनुसार
2.	अनुमोदित दरमानों पर राजस्व आकलन (लाख रु. में)	19979.63	प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए फार्म III के अनुसार
3.	<b>एआरआर के संदर्भ में घाटा (लाखों रु. में) (1-2)</b>	<b>23356.98</b>	
4.	वर्ष 2014-15 प्रहस्तित पीओएल की मात्रा (टन)	588074	प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए फार्म III के अनुसार
5.	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रति टन दर (रु.)	193.00	प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए फार्म III के अनुसार
6.	<b>प्राधिकरण अनुमोदित दरमानों पर आकलित घाट शुल्क (लाख रु. में) (4X5)</b>	1134.98	प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए फार्म III के अनुसार
	संशोधित प्रस्तावित दर (तटीय) (रु.)		
7.	पीओएल और पीओएल उत्पादों हेतु संशोधित प्रति टन	500.00	
	<b>वृद्धि</b>	<b>₹</b>	<b>%</b>
8.	प्रति टन घाट शुल्क (7-5) (अंतरीय वृद्धि)	307.00	159.07
	प्रस्तावित संशोधन से अतिरिक्त राजस्व		
9.	वृद्धिशील घाट शुल्क (लाख रु. में) (307 / टन x (4)	1805.39	
10.	प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् एआरआर के संदर्भ से घाटा (3-9)	21551.59	

10. बाद में, एमओपीटी ने 31 जुलाई, 2018 के इमेल के साथ मंडल के संकल्प की एक प्रति भेजी। मंडल ने अपने 26 जुलाई, 2018 के संकल्प संख्या 38 के द्वारा संशोधित प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्राधिकरण को पीओएल और पीओएल उत्पादों की वर्तमान घाट शुल्क दर को बढ़ा कर 500/-रु. प्रति टन करने का प्रस्ताव किया।

11. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध हैं। संबंधित पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके द्वारा प्रस्तुत किए तर्कों का सार-संक्षेप संबंधित पक्षकारों को अलग से भेजा जाएगा। यह ब्यौरा हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

12. मामले में संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर निम्नलिखित सूचना उभर कर सामने आई है:-

(i) प्रशुल्क नीति 2015 के अनुसरण में मरमुगांव पत्तन न्यास (एमओपीटी) के वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार 17 नवंबर, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/38/2016-एमओपीटी के द्वारा अनुमोदित किये गए थे और 31 मार्च, 2019 तक वैध हैं। एमओपीटी का चालू प्रस्ताव एक मद अर्थात् पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) और पीओएल उत्पादों के घाट शुल्क में ऊपर की ओर संशोधन करने का है।

(ii) जैसा पहले के पैराओं में बताया गया है, पिछले संशोधन के दौरान एमओपीटी की वार्षिक राजस्व अपेक्षा का आकलन 433.37 करोड़ रु. किया था। दरमानों में प्रस्तावित दरों पर एमओपीटी द्वारा आकलित राजस्व 199.80 करोड़ रु. था। नवंबर, 2016 के प्रशुल्क आदेश में, पत्तन द्वारा यथाप्रस्तावित, 233.57 करोड़ रु. का आकलित राजस्व अनावरित रहने दिया गया।

पत्तन पर लौह अयस्क और कोयला प्रहस्तन पर रोक लग जाने के कारण पत्तन द्वारा गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना करने को देखते हुए, एमओपीटी ने, एक परामर्शदाता की रिपोर्ट के आधार पर पीओएल और पीओएल उत्पादों की एक आरक्षित कार्गो के रूप में पहचान की जिसकी दर को आद्योपांत प्रभाव डाले बिना बढ़ाया जा सकता है। 14 मई, 2018 के आरम्भिक प्रस्ताव में एमओपीटी ने पीओएल और पीओएल उत्पादों की वर्तमान घाट शुल्क दर को 193/-रु. प्रति टन से बढ़ा कर 1250/-रु. प्रति टन करने का प्रस्ताव किया था। प्रतिशत में यह वृद्धि 548% निकाली गई।

एमओपीटी ने वर्तमान दरमान की संशोधित अनुसूची 2.1.3 तरल कार्गो भेजी। यह देखा जाता है कि संशोधित अनुसूची में एमओपीटी द्वारा चाहा गया संशोधन पहली कार्गो मद अर्थात् पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक तथा पीओएल उत्पादों की घाट शुल्क दर में है। उक्त अनुसूची में अन्य तरल कार्गो की घाट शुल्क दर में यथास्थिति बनाये रखी गई है।

(iii) पीओएल और पीओएल उत्पादों पर 1250/-रु. प्रति टन की प्रस्तावित घाट शुल्क दर की प्रस्तावित घाट शुल्क दर पर तेल कंपनियों नामतः हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने भारी आपत्ति की जैसा कि पहले चर्चा की गई है।

एमओपीटी ने तेल कंपनियों की आपत्तियों पर कोई टिप्पणी नहीं की। तथापि, पत्तन ने उसके द्वारा चाही गई वृद्धि पर औचित्य जरूर प्रस्तुत किया जिस पर आगामी पैराओं में चर्चा की जायेगी।

(iv) प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 2.6 के अनुसार, सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा के आधार पर महापत्तन न्यासों को यह अधिकार होगा कि वह अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार बाजार की ताकतों का मुकाबला करने के लिए दरों का निर्धारण करें। यद्यपि, प्रशुल्क नीति 2015 में महापत्तन न्यासों को शिथिलता उपलब्ध है, तेल कंपनियों की भारी आपत्तियों को देखते हुए, मरमुगांव पत्तन न्यास को पीओएल और पीओएल उत्पादों के लिए 1250/- रु. प्रति टन की प्रस्तावित घाटशुल्क दर के समर्थन में लागत विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। एमओपीटी ने बताया कि प्रस्तावित दर लागत के आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन, पत्तन ने घाट शुल्क दर में प्रस्तावित वृद्धि के लिए औचित्य दिये जिन पर आगामी पैराओं में चर्चा की जा रही है।

(v) तेल कंपनियों द्वारा उठायी गई आपत्तियों के मद्देनजर पत्तन को एचपीसीएल, आईओसीएल तथा बीपीसीएल के साथ बैठकर पीओएल कार्गो की घाटशुल्क दर की मात्रा में सामंजस्य स्थापित करने का अनुरोध किया गया। पत्तन द्वारा तेल कंपनियों के साथ 3 जुलाई, 2018 को बुलाई गई कथित बैठक में, पत्तन ने सूचित किया है कि, तेल कंपनियों ने 31.03.2019 तक घाटशुल्क की वर्तमान दर को ही जारी रखने और उसके पश्चात् 5% से 10% की वृद्धि पर सुविचार करने का अनुरोध किया। चूंकि पत्तन और तेल कंपनियों में वृद्धि की प्रमात्रा पर कोई सहमति नहीं बनी और यह प्रयास भी निष्फल रहा, इसलिए पत्तन ने 1250/-रु. प्रति टन की मूल प्रस्तावित दर की समीक्षा की और 25 जुलाई 2018 के संशोधित प्रस्ताव में इसे घटाकर 500/-रु. प्रति टन कर दिया। संशोधित प्रस्तावित दर पर वृद्धि मूल

प्रस्ताव में चाही गई 548% के प्रति 159% निकलती है। पत्तन ने न्यासी मंडल के संशोधित घाट शुल्क दर को बढ़ा कर 500/-रु. प्रति टन करने के अनुमोदन की एक प्रति भेजी। पत्तन ने घाटशुल्क दर में प्रस्तावित वृद्धि के निम्नलिखित औचित्य दिये हैं:-

- (क) लौह अयस्क खनन प्रतिबंधित कर दिया गया है और एसडब्ल्यूपीएल द्वारा भी गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रचालन के निलंबन को ध्यान में रखकर कोयले का प्रहस्तन भी रोक दिया गया है। पत्तन ने फरवरी 2018 से पिछले 5 महीनों में कोयला कार्गो का प्रहस्तन नहीं किया है। पत्तन वित्तीय दबाव में है और व्यय को वहन करने यहां तक कि पत्तन कर्मचारियों का वेतन तक देने में भी असमर्थ हो गया है। पत्तन की संचयी हानि 563 करोड़ रुपए हो गई है।
- (ख) पत्तन को 1700 कर्मचारियों को वेतन और 4300 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान करना पड़ता है। पत्तन लागतें घटने के लिए अपने कर्मचारियों की लौह अयस्क और कोयला व्यापार के अन्य हितधारकों की तरह कामबंदी नहीं कर सकता और उसे बड़े कार्यबल को बनाये रखना है जो एक स्थायी लागत है।
- (ग) पत्तन का पेंशनर पर व्यय प्रति वर्ष लगभग 100.00 करोड़ रुपए है जिस पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। अपने कर्मचारियों पेंशनरों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने पर पत्तन का व्यय प्रति वर्ष लगभग 18.00 करोड़ रुपए तक का है।
- (घ) पत्तन लौह अयस्क और कोयला प्रहस्तन पर रोक के कारण गंभीर वित्तीय संकट में है। इस परिदृश्य में, पीओएल कार्गो की दर में वृद्धि के सिवा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। यदि पत्तन किसी अन्य कार्गो के हमारे पत्तन से अपरिवर्ती हो जायेगा।
- (ङ) पीओएल दरों में वृद्धि से कार्गो पर आद्योपांत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पत्तन की वर्तमान वित्तीय स्थिति पीओएल की घाट शुल्क दरों में वृद्धि चाहती है।
- (च) पीओएल और पीओएल उत्पादों की घाट शुल्क दर में प्रस्तावित वृद्धि कुछ हद तक पत्तन के राजस्व में बढ़ोत्तरी करेगी।
- (छ) 500/- रु. प्रति टन की संशोधित प्रस्तावित दर से प्रति लीटर घाट शुल्क 0.50 पैसे प्रति लीटर होगा। जिसे पीओएल पर करें और शुल्कों को देखते हुए प्रयोक्ताओं द्वारा वहनीय है।
- (ज) पीओएल एक स्वच्छ कार्गो है और गोवा में इसकी कीमतें देश भार से कम हैं। स्वच्छ गोवा के लिए 0.50 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि बहुत छोटी सी कीमत है।
- (झ) एमओपीटी के प्रस्ताव के अनुसार कवर न किया गया एआरआर, पिछले प्रशुल्क आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा पहले से अनुमोदित 233.57 करोड़ रु. का है। 500/-रु. प्रति टन के संशोधित प्रस्तावित दर पर 18.05 करोड़ रु. मात्र ही कवर हो पायेगा। तब भी 215.52 करोड़ रु. का घाटा रह जाता है।
- (ञ) प्रस्तावित दर अधिकतम दर होगी और व्यापारिक परिदृश्य में परिवर्तन के साथ रियायतें दी जा सकती हैं।
- (vi) (क) इस प्रकार, संक्षेप में, गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गोवा में लौह अयस्क और कोयला प्रहस्तन पर रोक लगा देने की वजह से दर में प्रस्तावित संशोधन करना पड़ रहा है। एमओएस द्वारा जारी प्रशुल्क नीति 2015 पत्तन को एआरआर के भीतर शिथिलता प्रदान करती है। महापत्तन न्यास अधिनियम (एमपीटी) की धारा 111 के अंतर्गत एमओएस द्वारा जारी प्रशुल्क नीति 2015, इस प्राधिकरण पर बाध्यकर है। यह उल्लेखनीय है कि मामले की परामर्शी प्रक्रिया के दौरान इस प्राधिकरण के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए एमओपीटी वृद्धि को 1250/- रु. प्रति टन से घटाकर 500/- रु. प्रति टन तक ले आया। पत्तन द्वारा सूचित की गई स्थिति को मान्य करते हुए कि उनके पास वेतन और पेंशन भुगतान के लिए भी निधियां मौजूद नहीं हैं और इस बात को भी मान्य करते हुए कि प्रस्तावित वृद्धि पत्तन की स्थिरता के लिए एक अंतरिम व्यवस्था है न कि लाभप्रदता अर्जित करने की मंशा से, और इस बात को भी मान्य करते हुए कि न्यासी मंडल ने भी प्रस्तावित 500/-रु. प्रति टन की संशोधित घाटशुल्क दर का अनुमोदन किया है, प्रस्तावित 500/-रु. प्रति टन की संशोधित घाटशुल्क दर का अनुमोदन यह प्राधिकरण पीओएल और पीओएल उत्पादों के लिए एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर 193/-रु. प्रति टन की वर्तमान घाट शुल्क दर से बढ़ा कर पत्तन द्वारा प्रस्तावित 500/-रु. प्रति टन की संशोधित घाटशुल्क दर का अनुमोदन करता है। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें अधिकतम दर होती हैं और पत्तन को उससे कम दर प्रभारित करने की शिथिलता प्राप्त होती है। इस उपबंध का हवाला देते हुए, पत्तन ने यह भी बताया है कि व्यापारिक परिदृश्यों में परिवर्तन के आधार पर रियायत दी जा सकती है।

1250/- रु. प्रति टन की मूल प्रस्तावित दर पर तेल कंपनियों ने आपत्ति उठाते हुए, यह उल्लेख किया कि वे अन्य विकल्पों की तलाश करेंगे। पत्तन की यह राय है कि पीओएल दरें कार्गो पर आद्योपांत प्रभाव नहीं डाल सकतीं। प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 2.7 के अनुसार, दरमानों में किसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, पत्तन को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि पत्तन को यातायात की हानि न हो। पत्तन व्यापारिक परिदृश्य में परिवर्तनों के आधार पर दर में रियायत देने को सहमत है।

एमओपीटी के दरमानों की आगामी समीक्षा 1 अप्रैल 2019 से अपेक्षित है। पत्तन द्वारा प्रस्तावित भारी वृद्धि पर वर्तमान कार्यवाही के दौरान तेल कंपनियों द्वारा उठायी गई आपत्तियों और उनके द्वारा यह कहते हुए कि उन्हें पाइपलाइन/सड़क मार्ग द्वारा परिवहन के अन्य विकल्प तलाशने पड़ेंगे को ध्यान में रखकर पत्तन को यह सलाह दी जाती है कि 1 अप्रैल 2019 से दरमानों की अपेक्षित समीक्षा करते समय पीओएल और पीओएल उत्पादों की संवर्धित घाटशुल्क दर की समीक्षा करें क्योंकि वर्तमान प्रक्रिया पत्तन द्वारा सूचित की गई वित्तीय समस्या को देखते हुए महज एक अंतरिम व्यवस्था है।

(ख) पत्तन ने प्रति वर्ष 18.05 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व का आकलन किया है (यानी 307/- रु. प्रति टन की वृद्धिशील घाट शुल्क दर X 588074 टन)। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि जब तक यह आदेश प्रभावी होगा तब तक सितंबर 2018 के आस-पास का समय होगा। अतः यदि वर्ष 2018-19 के सात महीनों के लिए यथानुपातिक यातायात पर सुविचार किया भी जाता है, तो अतिरिक्त राजस्व 10.53 करोड़ रु. बैठता है (यानी 307/- रु. प्रति टन की वृद्धिशील घाट शुल्क दर X 340343 टन)। जैसा पत्तन ने बताया है, अतिरिक्त राजस्व 233.5.7 करोड़ रु. के भीतर ही है जिसे पिछले प्रशुल्क संशोधन आदेश में कवर नहीं किया गया छोड़ दिया गया था। यहां तक कि प्रस्तावित वृद्धि की मंजूरी दे देने के पश्चात् भी, नवंबर 2016 आदेश में आकलित एआरआर का 223.04 करोड़ रु. अपूरित रह जायेगा।

(vii) सामान्यतः इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर भारत के राजपत्र में दरमानों की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होती है। तथापि, चूंकि एमओपीटी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, अनुमोदित संशोधित दर राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी की जाती है। संशोधित दर की वैधता एमओपीटी के वर्तमान दरमानों की वैधता के साथ सह-समाप्य की जाती है, जो 31 मार्च, 2019 तक है।

13.1. परिणाम में और ऊपर दिए गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण एमओपीटी के वर्तमान दरमानों में पेट्रोलियम, तेल और स्नेहकों तथा पीओएल उत्पादों के लिए निम्नलिखित संशोधित घाट शुल्क दर को अनुमोदित करता है:-

(i) बर्थ पर पेट्रोलियम, तेल व स्नेहकों तथा पीओएल उत्पादों के लिए घाट शुल्क दर, अनुसूची 2.1.3 – तरल बल्क कार्गो के अंतर्गत क्रमांक 1 – 2 के अंतर्गत निर्धारित – एमओपीटी के वर्तमान दरमानों में कार्गो संबंधी प्रभारों को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:

**2.1.3 तरल बल्क कार्गो की अनुसूची:**

क्र.सं.	वस्तुओं का विवरण	यूनिट	विदेशी दर (रु. में)	तटीय दर (रु. में)
1.	पेट्रोलियम, तेल और स्नेहकों तथा पीओएल उत्पाद	प्रति टन	500.00	500.00

13.2. इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से तत्काल प्रभाव से लागू होगी।  
**अनुमोदित दर एमओपीटी के वर्तमान दरमानों की वैधता की तारीख तक वैध होंगी यानी 31 मार्च, 2019 तक।**

13.3. एमओपीटी को वर्तमान दरमानों में तदनुसार संशोधन करने का निदेश दिया जाता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/18]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION**

Mumbai, the 6th August, 2018

**No. TAMP/39/2018-MOPT.**— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mormugao Port Trust (MOPT) for Revision of Wharfage Charges on POL and POL Products as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports****Case No. TAMP/39/2018-MOPT****Mormugao Port Trust**

- - -

**Applicant****QUORUM**

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**(Passed on this 31<sup>st</sup> day of July 2018)

This case relates to the proposal received from Mormugao Port Trust (MOPT) vide its letter no. FA/Cost/125/2018/41 dated 14 May 2018 for revision of Wharfage Charges on POL and POL Products.

2.1. This Authority had vide Order No.TAMP/38/2016-MOPT dated 17 November 2016 passed an Order disposing of the proposal of MOPT for general revision of port's Scale of Rates (SOR). The revised SOR and Performance Standards approved by this Authority vide Order No.TAMP/38/2016-MOPT dated 17 November 2016, was notified vide Gazette No.434 dated 30 November 2016. Subsequently, a speaking order was notified vide Gazette No.15 dated 12 January 2017. The SOR came into force after expiry of 30 days from the date of notification of the SOR and Performance Standards in the Gazette of India i.e. 30 December 2016. The validity of SOR is prescribed till 31 March 2019.

2.2. As stated in the said Order, the MOPT estimated annual revenue at ₹199.80 crores as against the estimated Annual Revenue Requirement (ARR) of ₹433.37 crores which left revenue requirement of ₹233.57 crores uncovered. The port had not proposed to fully cover the ARR. The revenue gap of ₹233.57 crores and the concession in tariff which the port has agreed to give for iron ore cargo was to be recovered from the revenue on account of increased volume of iron ore traffic. The tariff as proposed by MOPT was approved by this Authority in the Order dated 17 November 2016.

3.1. The port has now filed the proposal for revision in the wharfage rate of POL and POL Products. The main points made by the MOPT in its proposal dated 14 May 2018 are summarised below:

- (i) The Port vide its letter No: FA/Cost/125/2016/89 dated 30.06.2016 sent a proposal to TAMP for general revision of its SOR. As per the Tariff Policy, 2015, ARR was worked out to ₹433.36 crores and accordingly the SOR was drawn based on the overall traffic of 14.71 million tonnes for the year 2014-15.
- (ii) As per the working, an increase of 240% and 106% in the (then) existing SOR would have been required for Cargo Related Services (CRS) and Vessel Related Services (VRS) respectively to meet the ARR. However, such a huge increase in tariff would have affected the trade and hence the VRS charges were proposed to be increased by 35%, CRS charges and storage charges by 25%. The increase in charges was inclusive of 9% Special rate and hence the net increase was only 26% and 16% respectively for Vessel related charges and Cargo related charges.
- (iii) The TAMP vide Order No.TAMP/38/2016-MOPT dated 06 February 2017 approved the proposed SOR and same was notified in the Gazette of India Extraordinary on 12 January 2017 vide Gazette No.15. The revised SOR came into effect from 30 December 2016 and is in force till 31 March 2019.
- (iv) **Details of the Current Proposal:**

The Port is handling approximately 6 lakh tonnes of POL every year and the existing wharfage is ₹193/- per tonne. POL has been identified as a captive cargo whose rates can be increased without affecting the throughput. Therefore, it is proposed to increase the Wharfage rate on POL cargo to ₹1250/- per tonne.

(v) **Justification:**

- (a) The Port is facing severe financial crisis due to stoppage of iron ore and coal handling. Increase in the above rates would increase the Port's revenues to some extent. Port's present financial position warrants increase in wharfage rates of POL.
- (b) The deficit with respect to ARR as per the MOPT's proposal already approved by the Authority is ₹233.57 crores. The proposed increase in wharfage rate of POL would generate an additional revenue of only ₹62.16 crores, still having a deficit of ₹171.41 crores.
- (c) Increase in POL rates may not affect the cargo throughput.
- (d) The per litre cost would be around 1.25, which is affordable to users considering the taxes and duties levied on POL.

(vi) The revised wharfage rate for POL and POL products proposed in existing SOR by MOPT is as follows:

## 2.1.3. Liquid Bulk Cargo

Sr. No.	Particulars of Commodities	Rate per Tonne (₹.)	
		Foreign Cargo	Coastal Cargo
1.	Petroleum, Oil & Lubricants and POL Products	1250.00	1250.00
2.	Caustic Soda	86.00	51.60
3.	Liquid Ammonia	188.00	112.80
4.	Acids of all types	128.00	76.80
5.	LPG / LNG	350.00	210.00
6.	Edible Oil	86.00	51.60
7.	Molasses	57.00	34.20
8.	Any other liquid bulk cargo not specified above	126.00	75.60

[The increase is proposed only in respect of POL and POL products at Sl. No.1 from existing ₹193/ tonne to ₹1250/- per tonne for Sr. No. 2 to 8, no charge proposed by MOPT]

3.2. The proposal has been put up to the Board for Approval and the Board Resolution shall be submitted shortly. The Authority is requested to approve the revision in the wharfage of POL and POL Products to ₹1250/- per Tonne as shown in the table above. The effect of proposed revision in wharfage rate of POL and POL Products as furnished by MOPT is tabulated below:

Sr. No.	Particulars		Remarks
1.	ARR as per MOPT Proposal (₹ in Lakhs)	43336.61	As per Form I submitted to TAMP
2.	Revenue Estimation at approved SOR (₹ in Lakhs)	19979.63	As per Form III submitted to TAMP
3.	<b>Deficit w.r.t. ARR (₹. in Lakhs) (1-2)</b>	23356.98	
4.	POL Quantity Handled in 2014-15 (Tonnes)	588074	As per Form III submitted to TAMP
5.	Rate per Tonne approved by TAMP (₹)	193.00	As per Form III submitted to TAMP
6.	<b>Estimated Wharfage at TAMP approved SOR (₹. in Lakhs) (4X5)</b>	1134.98	As per Form III submitted to TAMP
	<b>Revised Rates Proposed (Coastal) (₹)</b>		
7.	Revised Wharfage per Tonne proposed for POL and POL products.	1250.00	
	<b>Increase</b>	₹	%
8.	Wharfage per Tonne (7-5) (Differential increase)	1057.00	547.67
	<b>Additional Revenue from Proposed Revision</b>		
9.	Incremental Wharfage (₹ in Lakhs) (₹1057/ tonne X 5.88 tonne)	6215.94	
10.	Deficit w.r.t. ARR after proposed Revision (₹ in Lakhs) (3-9)	17141.04	

4. The details of Wharfage at Berth for Liquid Bulk Cargo approved by the Authority in the schedule 2.1.3 of Order No.TAMP/38/2016-MOPT dated 17 November 2016 and the proposed amendment in the wharfage rate of POL and POL products sought by the MOPT is tabulated below:

Sr. No	Liquid Bulk Cargo Tariff approved by the Authority vide Order no.TAMP/38/2016-MOPT dated 17.11.2016.				Proposed amendment in rates proposed by MOPT vide its email dated 14.05.2018.			
	Sr. No.	Particulars of Commodities	Rate per Tonne (₹.)		Sr. No.	Particulars of Commodities	Rate per Tonne (₹.)	
			Foreign Cargo	Coastal Cargo			Foreign Cargo	Coastal Cargo
1.	1.	Petroleum, Oil & Lubricants and POL Products	193.00	193.00	1.	Petroleum, Oil & Lubricants and POL Products	1250.00	1250.00
	2.	Caustic Soda	86.00	51.60	2.	Caustic Soda	86.00	51.60
	3.	Liquid Ammonia	188.00	112.80	3.	Liquid Ammonia	188.00	112.80
	4.	Acids of all types	128.00	76.80	4.	Acids of all types	128.00	76.80
	5.	LPG / LNG	350.00	210.00	5.	LPG / LNG	350.00	210.00
	6.	Edible Oil	86.00	51.60	6.	Edible Oil	86.00	51.60
	7.	Molasses	57.00	34.20	7.	Molasses	57.00	34.20
	8.	Any other liquid bulk cargo not specified above	126.00	75.60	8.	Any other liquid bulk cargo not specified above	126.00	75.60

5.1. While acknowledging the proposal, the MOPT was vide our letter dated 17 May 2018 requested to forward a copy of the Board approval. The Port has not furnished copy of the Board approval.

5.2. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the proposal of MOPT dated 14 May 2018 was forwarded vide our letter dated 17 May 2018 to the concerned users/ user organisations seeking their comments. We received comments from Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) vide its email dated 22 May 2018 and Indian Oil Corporation Limited (IOCL) vide its letter dated 23 May 2018 and also letter dated 25 May 2018. The comments received from the HPCL and IOCL were forwarded to the MOPT as feedback information. The MOPT has not furnished its comments.

5.3. The HPCL and IOCL vide their email dated 22 May 2018 and 23 May 2018 requested for a meeting to discuss the subject proposal along with Industry Members, preferably during the first week of June 2018. In this regard, we have vide our letter dated 24 May 2018 communicated to HPCL and IOCL that as per the consultation process followed by the TAMP, an opportunity of hearing will be afforded during the Joint hearing to each of the users / user associations. The HPCL and IOCL were, therefore, requested to attend the Joint hearing and give observations / comments on the proposal at the joint hearing.

6. A joint hearing in this case was held on 14 June 2018 at the MOPT premises. The MOPT made a brief power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the MOPT and the concerned users/ user organizations including IOCL, HPCL and BPCL have made their submissions:

7.1. As agreed at the joint hearing, the MOPT was requested vide our letter dated 20 June 2018 to sit together with the HPCL, IOCL and BPCL and attempt to arrive at a consensus in the quantum of hike in wharfage rate of POL cargo and to respond in a week's time i.e. by 22 June 2018. This was followed by a reminder dated 27 June 2018.

7.2. Further, in the letter dated 27 June 2018, MOPT was requested to furnish the cost statement in support of proposed wharfage rate of ₹1250/- per tonne for Petroleum Oil and Lubricants and POL products. While furnishing the cost calculation, the general principle for apportionment of common expenses as in Form – 5 of the earlier tariff filing proposal is to be adopted by MOPT. For Case of reference, a copy of Form – 5 duly modified removing irrelevant items was also sent to MOPT. The MOPT was also requested to indicate the actual quantity of POL and POL products handled by MOPT in the year 2017-18 and projections for the year 2018-19. The MOPT was requested to furnish the requisite information positively by 1 July 2018.

8.1. With reference to the point of action decided at the joint hearing brought out at para 7.1 above, the MOPT vide its email dated 4 July 2018 has intimated that a Meeting with Oil PSUs was held on 3 July 2018 to arrive at a consensus of quantum of hike in wharfage rate of POL Cargo. A copy of the Minutes of the Meeting held on 03 July 2018 for revision of Wharfage Charges on POL Cargo at MOPT is furnished. The highlights of the said meeting are as under:

- (i) IOC stated that the increase in the proposed wharfage charges on POL cargo is not justifiable. Representatives of all the three companies requested to continue with current rate of wharfage (₹193/-

per MT) which is valid till 31.03.2019. Thereafter, hike of 5-10 % could be recommended for approval.

- (ii) Representative of oil companies also stated that if such a steep increase in wharfage charges on POL cargo is imposed then they will have to look for other alternate means of transportation and diversion of the cargo from the Port.
- (iii) Port has conveyed to the representatives of the Oil Companies that this increase in wharfage charges is temporary till the financial condition of the Port improves. It was further informed that the rate proposed is a ceiling rate which can be reduced depending upon the change in the market conditions. The Port does not want any cargo to be diverted, however, the precarious financial condition has compelled the Port to look for such measures that will help in sustaining the Port, even if marginally.
- (iv) The Port also offered not to revise the existing wharfage but levy an additional cess / charge which would be of a fixed tenure till the condition of the Port improves.
- (v) Representatives of Oil Companies informed that the oil companies would not be able to sustain this steep hike. They were requested to convey to their respective Head Offices that this increase wharfage charges on POL cargo is temporary till the financial condition of the Port improves and sought the support of the sister oil PSUs in this hours of financial crisis.

8.2. With reference to the point of action intimated vide our letter dated 27 June 2018 brought out in para 7.2. above, the MOPT vide its letter dated 30 June 2018 has submitted that the proposed Wharfage Rate of POL Cargo of ₹1250/- per MT is not justifiable on cost calculation. However, the rate is justifiable on the following grounds:

- (i) A Consultant appointed by Ministry of Shipping for suggesting measures for improvement of Port's profitability has suggested increase in POL charges.
- (ii) The proposed wharfage rate of ₹1250/- per MT is within the ARR of ₹433.36 crores worked out as per tariff revision guidelines, 2015.
- (iii) Port is in financial stress and unable to generate revenue due to ban on Iron ore mining and coal handling at berth no.6.
- (iv) Port has accumulated losses of ₹563 crores and has to pay salary to 1700 employees and pension to 430 pensioners.
- (v) POL is a clean cargo and the Port's handling cost per litre is ₹1.30/- (approx.)
- (vi) Presently, the taxes and duties levied on POL is 100% of the production cost and dealers margin is around ₹3/- per litre.
- (vii) Despite all such cost POL prices in Goa are least in the country. Hence, ₹1.30/- per litre is a small price to pay for clean Goa and it won't affect the demand.

9. Subsequently, the MOPT vide its letter dated 24 July 2018 has revised downwards the proposed wharfage rate from ₹1250/- per tonne to ₹500/- per tonne. The details of revised proposal are as under:

- (i) The port had submitted the proposal to TAMP for increasing the POL wharfage rate to ₹1250/- per tonne. Accordingly, TAMP conducted a joint hearing with all the stakeholders including the Oil Marketing Companies (OMCs). As there was no agreement between the Port and the OMCs TAMP advised to hold another meeting between MOPT and OMCs to arrive at a consensus on the quantum of increase, which again proved inconclusive.
- (ii) This issue was discussed with the Consultant and as per their report, a wharfage rate of ₹500/- per tonne could be levied on the POL cargo. Therefore, the Port wishes to revise the earlier proposal and decrease the proposed Wharfage on POL products from ₹1250/- per tonne to ₹500/- per tonne.
- (iii) POL has been identified as a captive cargo and it is not easy for the Oil companies to switch to other means for providing POL to the State of Goa. Therefore, the wharfage rates on the POL cargo can be increased without affecting the cargo throughput. Therefore, it is proposed to increase Wharfage on POL cargo from ₹193/- per tonne to ₹500/- per tonne. The Port is handling approximately 6 lakh tonnes of POL every year.

- (iv) (a) The Port is facing severe financial crises due to stoppage of iron ore and coal handling. Increase in the above rates would increase the Port's revenues to some extent.
- (b) The Port cannot lay off its employees unlike other stakeholders of the iron ore and coal trade, to reduce costs and has to maintain a large workforce which is a fixed cost.
- (c) The Port's outgo on pensioners is about ₹100.00 crores per annum on which it has absolutely no control.
- (d) The Port's outgo on the medical facilities provided to its employees, pensioners and their dependents is to the tune of ₹18.00 crores per annum.
- (e) The deficit with respect to ARR as per the MOPT's proposal already approved by TAMP is ₹233.57 crores whereas the proposed increase would generate an additional revenue of only ₹18.05 crores still having a deficit of ₹215.52 crores.
- (f) Increase in POL rates may not affect the cargo throughput.
- (g) Port's present financial position warrants increase in wharfage rates of POL.
- (h) The per litre wharfage would be ₹0.50 paise, which is affordable to users considering the taxes and duties levied on POL.
- (i) POL is a clean cargo and the POL prices in Goa are amongst the least in the country. Hence, ₹0.50 paise per litre is a small price to pay for a cleaner Goa.
- (j) The proposed rate will be the ceiling rate and concessions can be given depending on the changes in the business scenario.

The revised SOR is as under:

#### 2.1.3. Liquid Bulk Cargo:

Sr. No.	Particulars of Commodities	Rate per Tonne (₹)	
		Foreign Cargo	Coastal Cargo
1.	Petroleum, Oil & Lubricants and POL Products	500.00	500.00
2.	Caustic Soda	86.00	51.60
3.	Liquid Ammonia	188.00	112.80
4.	Acids of all types	128.00	76.80
5.	LPG / LNG	350.00	210.00
6.	Edible Oil	86.00	51.60
7.	Molasses	57.00	34.20
8.	Any other liquid bulk cargo not specified above	126.00	75.60

[The increase proposed by MOPT is only in respect of Sr. No.1]

- (v) The statement showing effect of proposed rate revision in POL Charges is given as below:

Sr. No.	Particulars		Remarks
1.	ARR as per MOPT Proposal (₹ in Lakhs)	43336.61	As per Form I submitted to TAMP
2.	Revenue Estimation at approved SOR (₹ in Lakhs)	19979.63	As per Form III submitted to TAMP
3.	<b>Deficit w.r.t. ARR (₹. in Lakhs) (1-2)</b>	<b>23356.98</b>	
4.	POL Quantity Handled in 2014-15 (Tonnes)	588074	As per Form III submitted to TAMP
5.	Rate per Tonne approved by TAMP (₹)	193.00	As per Form III submitted to TAMP
6.	<b>Estimated Wharfage at TAMP approved SOR (₹. in Lakhs) (4X5)</b>	<b>1134.98</b>	As per Form III submitted to TAMP

	<b>Revised Rates Proposed (Coastal) (₹)</b>		
7.	Revised Wharfage per Tonne proposed for POL and POL products.	500.00	
	<b>Increase</b>	<b>₹</b>	<b>%</b>
8.	Wharfage per Tonne (7-5) (Differential increase)	307.00	159.07
	<b>Additional Revenue from Proposed Revision</b>		
9.	Incremental Wharfage (₹ in Lakhs) (₹307/ tonne X (4))	1805.39	
10.	Deficit w.r.t. ARR after proposed Revision (₹ in Lakhs) (3-9)	21551.59	

10. Subsequently, the MOPT vide its email dated 31 July 2018 has forwarded a copy of its Board Resolution vide Resolution No.18 dated 26 July 2018 approving revised proposal to TAMP for upward revision in wharfage rate of POL and POL Products at ₹500/- per tonne.

11. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

12. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case the following position emerges:

- (i) The existing Scale of Rates (SOR) of the Mormugao Port Trust (MOPT) following the Tariff Policy, 2015 was last approved by this Authority vide Order No.TAMP/38/2016-MOPT dated 17 November 2016 and is valid till 31 March 2019. The current proposal of the MOPT is for upward revision in the wharfage rate for one item i.e. Petroleum Oil and Lubricants (POL) and POL products.
- (ii) As stated in the earlier paragraphs, the Annual Revenue Requirement (ARR) estimated by the MOPT during the last tariff revision was to the tune of ₹433.37 crores. The revenue estimated by the MOPT at the proposed rates in the SOR was ₹199.80 crores. An estimated ARR of ₹233.57 crores was left uncovered in the tariff Order of November 2016 as proposed by the port.

In view of severe financial crisis faced by the port due to stoppage of iron ore and coal handling at its port, the MOPT has, based on the report of the Consultant, identified POL and POL products as a captive cargo whose rates can be increased without affecting the throughput. In the initial proposal dated 14 May 2018, the MOPT had proposed to increase the wharfage rate of POL and POL products from the existing ₹193/- per tonne to ₹1250/- per tonne. The increase in terms of percentage worked out to 548%.

The MOPT has forwarded the revised schedule 2.1.3. – Liquid Cargo of the existing SOR. It is seen from the revised schedule that the revision sought by the MOPT is in the wharfage rate for the first cargo item i.e. Petroleum, Oil & Lubricants and POL Products. The wharfage rate for other liquid cargo in the said schedule are maintained at status quo.

- (iii) The proposed increase in the wharfage rate for POL and POL products at ₹1250/- per tonne was vehemently objected by the oil companies viz. the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) and Indian Oil Corporation Limited (IOCL) as brought out earlier.
- (iv) As per Clause 2.6. of Tariff Policy 2015, the Major Port Trusts have the flexibility to determine the rates to respond to the market forces based on commercial judgment and draw the SOR within the ceiling of indexed ARR. Though this flexibility is available to Major Port Trusts in the Tariff Policy 2015, in view of strong objections made by oil companies, the MOPT was requested to furnish the cost statement in support of proposed wharfage rate of ₹1250/- per tonne for Petroleum Oil and Lubricants and POL products. The MOPT has, stated that the proposed rate is not justifiable based on cost. The port has, however, furnished its justification for the proposed increase in the wharfage rate which is brought out in the subsequent paragraphs.
- (v) In view of the objection raised by the oil companies, the port was requested to sit together with the HPCL, IOCL and BPCL and attempt to arrive at a consensus in the quantum of hike in wharfage rate of POL cargo. In the said meeting convened by the port with the oil companies on 3 July 2018, the port has reported that oil companies requested to continue with current rate of wharfage which is valid till 31.03.2019 and thereafter consider hike of 5% to 10 %. As there was no agreement between the Port and the Oil Companies to arrive at a consensus on the quantum of increase and the attempt proved inconclusive, the port has reviewed the original proposed rate of ₹1250/- per tonne and reduced it to ₹500/- per tonne in its revised proposal dated 25 July 2018. At the revised proposed rate, the increase works out to 159% as against 548% increase sought in the original proposal. The Port has

forwarded a copy of the approval of its Board of Trustees approving the revised proposed wharfage rate of ₹500/- per tonne. The port has furnished the following justification for the proposed increase in the wharfage rate:

- (a) Iron ore mining is banned and Coal handling at port as well as by SWPL has been stopped in view of suspension of operations by Goa Pollution Control Board. The port has not handled coal cargo for the last five months since February 2018. Port is in financial stress and unable to generate revenue to meet the expenditure and even salary of port employees. Accumulated losses of port is to the tune of ₹563 crores.
  - (b) Port has to pay salary to 1700 employees and pension to 4300 pensioners. The Port cannot lay off its employees unlike other stakeholders of the iron ore and coal trade, to reduce costs and has to maintain a large workforce which is a fixed cost.
  - (c) The Port's outgo on pensioners is about ₹100.00 crores per annum on which it has absolutely no control. The Port's outgo on the medical facilities provided to its employees, pensioners and their dependents is to the tune of ₹18.00 crores per annum.
  - (d) Port is facing severe financial crisis due to stoppage of iron ore and coal handling. In this scenario, port is left with no other alternative but to increase the rate for POL cargo. If port increases rate for any other cargo, cargo will be diverted from our port.
  - (e) Increase in POL rates may not affect the cargo throughput. Port's present financial position warrants increase in wharfage rates of POL.
  - (f) Proposed increase in the wharfage rate of POL and POL products would increase the Port's revenues to some extent.
  - (g) The per litre wharfage would be 0.50 paise per litre at the revised proposed rate of ₹500/- per tonne, which is affordable to users considering the taxes and duties levied on POL.
  - (h). POL is a clean cargo and the POL prices in Goa are amongst the least in the country. Hence, ₹0.50 paise per litre is a small price to pay for a cleaner Goa.
  - (i) The ARR uncovered as per the MOPT's proposal already approved by this Authority in the last tariff Order is to the tune of ₹233.57 crores. At the revised proposed rate of ₹500/- per tonne, the port would generate an additional revenue of only ₹18.05 crores. Still, there will have a deficit of ₹215.52 crores.
  - (j) The proposed rate will be the ceiling rate and concessions can be given depending on the changes in the business scenario.
- (vi) (a) Thus, in short the revision in the wharfage rate proposed by the MOPT is due to severe financial crisis faced by the port on account of ban in handling of iron ore and coal in Goa by the Goa Pollution Control Board. The Tariff Policy, 2015 issued by the MOS gives flexibility to the Port to propose rates within the ARR. The additional revenue estimated at the proposed rate is well within the ARR. The Tariff Policy, 2015 issued by the MOS under Section 111 of the Major Port Trust (MPT) Act is binding on this Authority. It is noteworthy that in view of the efforts taken by this Authority during the consultation proceedings of the case, the MOPT has brought down the increase from ₹1250/- to ₹500/- per tonne. Recognising the position reported by the port that they do not have funds even to pay the salaries and pension payment and also recognising that the proposed increase is a stop gap arrangement for sustainability of the port and not with the intention for generating profitability, and also recognising that the Board of Trustees have also approved the revised proposed rate of ₹500/- per tonne, this Authority approves the revised wharfage rate for POL and POL products proposed by the port at ₹500/- per tonne from the existing wharfage rate of ₹193/- per tonne as a stop gap arrangement. The rate approved by this Authority are ceiling rate and the port has the flexibility to charge lower rate. Referring to this provision, the port has also stated that concessions can be given depending on the changes in the business scenario.

The oil companies while objecting on the original proposed rate of ₹1250/- per tonne have made a mention that they may have to look at the other alternatives. The Port is of the view

that the increase in POL rates may not affect the cargo throughput. As per clause 2.7 of the Tariff Policy 2015, it is for the port to ensure that as a result of any change in SOR, there will not be loss of traffic to the Port. The Port has already agreed to give concession in rate based on changes in the business scenario.

The next revision of the SOR of the MOPT is due from 1 April 2019. In view of the objection made by the oil companies during the current proceedings at steep increase proposed by the port and stating that it may have to look for alternative mode of transport by pipeline/ road, the port is advised that while revising the SOR due from 1 April 2019, the port may like to review the increased wharfage rates for POL and POL products as this exercise is only a stop gap arrangement to tide over the severe financial crisis reported by the port.

- (b) The port has estimated additional revenue of ₹18.05 crores per annum (i.e. ₹307/- per tonne incremental wharfage rate x 588074 tonnes). It is relevant to state that by the time this Order comes into effect, it will be around September 2018. So, if the prorated traffic is considered for seven months for the year 2018-19, the additional revenue will be ₹10.53 crores (i.e. ₹307/- per tonne incremental wharfage rate x 340343 tonnes). As stated by the port, the additional revenue is well within ARR of ₹233.57 crores which was left uncovered in the last tariff revision Order. Even after granting the proposed increase, ₹223.04 crores of the ARR estimated in the November 2016 Order is expected to remain uncovered.
- (vii) Ordinarily the rate approved by this Authority shall come into force after expiry of 30 days from the date of notification of the SOR in the Gazette of India. However, since MOPT is facing financial crisis, the revised rate approved is made effective from the date of notification of the Order in the Gazette. The validity of the revised rate is prescribed co-terminus with the validity of the existing SOR of MOPT which is till 31 March 2019.

13.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the following revised wharfage rate for Petroleum, Oil & Lubricants and POL Products in the existing SOR of the MOPT:

- (i) Wharfage rate for Petroleum, Oil & Lubricants and POL Products at berth at Sr. No 1, under Schedule 2.1.3 - Liquid Bulk Cargo prescribed under 2 – Cargo related charges in the existing SOR of MOPT is revised as follows:

#### 2.1.3 SCHEDULE OF LIQUID BULK CARGO:

Sr. No.	Particulars of commodities	Unit	Foreign rates (in ₹)	Coastal rates (in ₹)
1.	<b>Petroleum, Oil &amp; Lubricants and POL Products</b>	Per Tonne	500.00	500.00

13.2. The rate approved by this Authority shall come into effect immediately from the date of notification of the Order in the Gazette of India. The approved rate will be valid till the validity of the existing SOR of the MOPT i.e. till 31 March 2019.

13.3. The MOPT is directed to amend the existing SOR accordingly.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./188/18]